



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]  
No. 188]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2006/श्रावण 17, 1928  
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2006/SRAVANA 17, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग भंगालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिवेशालय)

जांच शुल्कात संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2006

(निर्णायक समीक्षा)

**विषय :** कोरिया गणराज्य और तुर्की के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आंशिक रूप से विन्यासित यार्न पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा की शुरुआत।

सं. 15/21/2006-डीजीएडी.—निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क की वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1955 को ध्यान में रखते हुए, उपशीर्ष 5402.42 के तहत आने वाले कोरिया गणराज्य (कोरिया आर पी) और तुर्की (जिन्हें संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आंशिक रूप से विन्यासित यार्न (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा जाएगा) के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश की थी। प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 23 नवम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/1/2001 - डी जी ए डी द्वारा प्रकाशित किया गया था एवं संबद्ध वस्तुओं पर दिनांक 27 दिसम्बर, 2001 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं 131/2001-सीमाशुल्क के अनुसार अनंतिम शुल्क लगाया गया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 16 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं 36/1/2001-डी जी ए डी द्वारा अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित किया था और 12 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना सं 97/2002 सीमाशुल्क के अनुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था।

## 2. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद, कोरिया गणराज्य और तुर्की के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आंशिक रूप से विन्यासित यार्न (जिसे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) है। आंशिक रूप से विन्यासित यार्न को वाणिज्यिक एवं बाजारी बोलचाल में सामान्यतः "पी ओ वाई" कहा जाता है तथा इस जांच में भी इसे पी ओ वाई कहा गया है। पी ओ वाई, पॉलिस्टर का एक यार्न होता है और विभिन्न क्षेत्रों की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु इसका विनिर्माण 50 डेनियर से 530 डेनियर की व्यापक रेज में किया जाता है। डेनियर, यार्न की शुद्धता का मापक है। डेनियर जितना कम होगा, यार्न उतना ही परिष्कृत होता है। पी ओ वाई एक मध्यवर्ती है, जिसे बुनाई अथवा कपड़ों में बुनने के योग्य बनाने के लिए आगे और प्रसंस्कृत (उदाहरणतः टेक्सचरिंग अथवा ड्रॉ-ट्रिवर्सिंग) किया जाता है। पी ओ वाई, पी एफ वाई (सीमाशुल्क वर्गीकरण 5402.43 के तहत वर्गीकृत) से स्वरूप में अलग है तथा पी एफ वाई वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र के भीतर नहीं है। चूंकि वर्तमान जांच एक समीक्षा जांच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही है, जिसका विवरण मूल जांच में दिया गया था और उसके पश्चात उत्पाद में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। तथापि यह वर्गीकरण संकेतात्मक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

## 3. जांच की शुरूआत

मै0 एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री (ए एस एफ आई) ने मै0 अपोलो फाइबर्स लि�0, मै0 सेंचुरी एन्का लि�0, मै0 सेंट्रल इंडिया पॉलिएस्टर्स लि�0, मै0 फिलाटेक्स इंडस्ट्रीज लि�0, मै0 इंडोरामा सिंथेटिक्स (आई) लि�0, मै0 गार्डन सिल्क मिल्स लि�0, मै0 जे बी एफ लि�0, मॉर्डन पेट्रोफिल्स, मै0 रेक्रोन सिंथेटिक्स लि�0 और मै0 वेलस्पन सिटेक्स लि�0 की ओर से कोरिया गणराज्य (कोरिया आर पी) और तुर्की के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा की आवश्यकता का प्रमाण देते हुए संयुक्त रूप से एक याचिका दायर की है। अपनी याचिका में, ग्राहिकाकर्ताओं ने प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के साथ यह दावा किया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है और ऊपर उल्लिखित अधिसूचनाओं के तहत आगे और 5 वर्षों की अवधि के लिए संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लागू रखने का अनुरोध किया है।

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा की जानी अपेक्षित है। प्रमाण सहित याचिका की जांच के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह मानना है कि सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 यथासंशोधित की धारा 9 क (5) के प्रावधान के तहत इस स्तर पर सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णयिक समीक्षा करना उचित होगा।

#### **4. शामिल देश**

वर्तमान जांच में शामिल देश कोरिया गणराज्य (कोरिया आर पी) और तुर्की (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश भी कहा जाएगा) हैं।

#### **5. प्रक्रिया**

दिनांक 16 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं0 36/1/2001-डी जी ए डी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम तथा दिनांक 12 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना सं0 97/2002 - सीमाशुल्क द्वारा लगाए गए अंतिम शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेने के पश्चात प्राधिकारी इस बात की समीक्षा करने के लिए कि सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आंशिक रूप से विन्यासित यार्न के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है अथवा नहीं, एतद्वारा समीक्षा प्रारंभ करते हैं।

समीक्षा में दिनांक 16 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं0 36/1/2001-डी जी ए डी के सभी पहलू शामिल हैं। मूल जांच में मै0 एसोसिएशन ऑफ़ सिथेटिक फाइबर इंडस्ट्री (ए एस एफ आई) ने मै0 सेंचुरी एंका लि�0, मै0 रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि�0 और मै0 सांघी पॉलिस्टर्स लि�0, मै0 रेमड सिथेटिक्स लि�0 और मै0 जे सी टी लि�0 की ओर से घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व किया था। निर्णयक समीक्षा में, मै0 अपोलो फाइबर्स लि�0, मै0 सेंचुरी एन्का लि�0, मै0 सेंट्रल इंडिया पॉलिस्टर्स लि�0, मै0 फिलाटेक्स इंडस्ट्रीज लि�0, मै0 इंडोरमा सिथेटिक्स (आई) लि�0, मै0 गार्डन सिल्क मिल्स लि�0, मै0 जे बी एफ लि�0, मै0 रेक्रॉन सिथेटिक्स लि�0 और मै0 वेलस्पन सिटेक्स लि�0 की ओर से मै0 एसोसिएशन ऑफ़ संथेटिक्स फाइबर इंडस्ट्री (ए एस एफ आई) द्वारा याचिका

दायर की गई है। मैं रिलायन्स इंडस्ट्री लिंग (आर आई एल), मैं सांघी इंडस्ट्रीज लिंग, मैं नोवा पेट्रोकेमिकल्स लिंग, मैं गोकुलानन्द पेट्रोफाइबर्स, मैं आफीज इंडस्ट्रीज लिंग, मैं राजवी पेट्रोकेम फी लिंग और मैं नाकोडा टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज लिंग द्वारा भी याचिका का समर्थन किया गया है। प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमों के अनुसार घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में प्रमुख हिस्सा रखने वाले याचिकाकर्ताओं पर भी विचार करने का प्रस्ताव किया है।

#### 6. जांच की अवधि

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 (12 महीने) तक की है। तथापि क्षति जांच की अवधि में जांच की अवधि सहित उसके पूर्व 1 अप्रैल, 2002 से जांच की अवधि की समाप्ति तक तीन वर्ष की अवधि शामिल है।

#### 7. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों में निर्यातकों और भारत में स्थित दूतावासों/उच्चायोंगों के माध्यम से उनकी सरकारों, भारत में उनके ज्ञात संबद्ध आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को संगत सूचना, निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी जी ए डी)

कमरा सं 240

उद्योग भवन

नई दिल्ली-110011

अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संगत अपने निवेदन प्रस्तुत कर सकती है।

### 8. समय-सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित रूप में भेजा जाए जो उपरोक्त पते पर प्राधिकारी के पास इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा सूचना अपूर्ण है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों अनुसार अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

### 9. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार, कोई हितबद्ध पार्टी अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

क्रिस्टी एल. फेर्नान्डेज, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

२४३७ GI/०६-२

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th August, 2006

(Sunset Review)

**Subject : Initiation of Sunset Review regarding anti-dumping duty imposed on Partially Oriented Yarn (POY) originating in or exported from Republic of Korea and Turkey.**

No. 15/21/2006-DGAD.— The Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended imposition of provisional Anti Dumping duty on imports of Partially Oriented Yarn (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Republic of Korea (Korea RP) and Turkey (also referred to as subject countries) falling under Sub-heading 5402.42. The preliminary findings were published vide Notification No 36/1/2001-DGAD dated 23rd November 2001 and provisional duty was imposed on the subject goods vide Customs notification No. 131/2001-Customs dated 27<sup>th</sup> December 2001. The Designated Authority came out with final findings on 16<sup>th</sup> August 2002 vide notification no 36/1/2001-DGAD and definitive anti dumping duty was imposed by Customs as per notification No. 97/2002-Customs dated 12<sup>th</sup> September 2002.

**2. Product under Consideration**

The Product Under Consideration in the present investigation is Partially Oriented Yarn (also referred to as subject goods), originating and exported from Korea RP and Turkey. Partially Oriented Yarn is generally known as "POY" in the commercial and market parlance and has also been referred to as POY in this investigation. POY is a yarn of polyester and is made in wide range from 50 Denier to 530 Denier to meet the requirement of different segments. Denier relates to the fineness of the yarn, lower the denier, finer the yarn. POY is an intermediate, which is subject to further processes (e.g. texturing or draw-twisting) to make it suitable for weaving or knitting into fabrics. POY is different form PFY (having custom classification 5402.43) and PFY is not within the scope of the present

investigations. Present investigation being a review investigation, product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation and there has been no significant development in the product during the period thereafter. The classification is, however, indicative and in no way binding on the scope of the present investigations.

### 3. Grounds for review and initiation

M/s Association of Synthetic fiber industry (ASF) on behalf of M/s Apollo Fibres Ltd., M/s Century Enka Ltd., M/s Central India Polyesters Ltd., M/s Filatex Industries Ltd., M/s Indorama Synthetics (I) Ltd., M/s Garden Silk Mills Ltd., M/s JBF Ltd., Modern Petrofils, M/s Recron Synthetics Ltd and M/s Welspun Syntex Ltd. have jointly filed an application substantiating the need for review of the antidumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from Republic of Korea (Korea RP) and Turkey. In their application, the petitioners have claimed with *prima facie* evidence that cessation of anti dumping duty imposed on subject goods from subject countries is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury and have requested to continuation and enhancement of the anti-dumping duty imposed on subject goods under the above mentioned notifications for a further period of 5 years.

The Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and the rules made there under require the Authority to review from time to time the need for continuance of anti dumping duty. On the basis of the examination of the duly substantiated application, The Designated Authority considers that the sunset review of the Anti-Dumping Duty imposed would be appropriate at this stage under the provision of section 9A (5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended..

### 4. Countries Involved:

The countries involved in the present investigations are Republic of Korea (Korea RP) and Turkey (also referred to as subject countries hereinafter).

### 5. Procedure

Having decided to review the final findings notified vide No. 36/1/2001-DGAD dated 16<sup>th</sup> August 2002 and final duty imposed by No. 97/2002-Customs dated 12<sup>th</sup> September 2002, the Authority hereby initiates investigations to review whether cessation of antidumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury on imports of Partially Oriented Yarn originating in or exported from subject countries, in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment & Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

2437 GI/06-3

The review covers all aspects of Notification No.36/1/2001-DGAD dated 16<sup>th</sup> August 2002. M/s Association of Synthetic fiber industry (ASFI) on behalf of M/s Century Enka Ltd., M/s Reliance Industries Ltd, M/s Sanghi Polysters Ltd, M/s Raymond Synthetics Ltd and M/s JCT Ltd represented domestic industry in the original investigations. In the sunset review, the application is filed by M/s Association of Synthetic fiber industry (ASFI) on behalf of M/s Apollo Fibres Ltd., M/s Century Enka Ltd., M/s Central India Polyesters Ltd., M/s Filatex Industries Ltd., M/s Indorama Synthetics (I) Ltd., M/s Garden Silk Mills Ltd., M/s JBF Ltd., Modern Petrofils, M/s Recron Synthetics Ltd and M/s Welspun Syntex Ltd. The application is also supported by M/s Reliance Industries Ltd (RIL), M/s Sanghi Industries Ltd, M/s Nova Petrochemicals Ltd, M/s Gokulanand petrofibers, M/s Affees Industries Ltd, M/s Rajvi Petrochem P Ltd and M/s Nakoda Textiles Industries Ltd. The Authority proposes to consider the petitioners who constitute the major proportion of the production of the subject goods in India to represent the domestic industry in accordance with the Rules supra.

#### 6. PERIOD OF INVESTIGATION

The period of investigation (POI) for the purpose of the present review is 1<sup>st</sup> April 2005 to 31<sup>st</sup> March 2006 (12 months). The period of injury examination would however include POI and three years prior to the POI i.e from 1<sup>st</sup> April 2002 to the end of POI.

#### 7. Submission of Information:

The exporters in subject country, their government through their Embassy/High Commission in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, (DGAD), Room No. 240, Udyog Bhavan, New Delhi-110011

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

#### 8. Time Limit

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of

publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

#### 9. Inspection of Public File:

In terms of Rules 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

CHRISTY L. FERNANDEZ, Addl. Secy. & Designated Authority